राज्यवार निर्मित राष्ट्रीय राजपथ

*369. **श्री चिरंजीव झा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे अभी तक राज्यवार कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजपथो का निर्माण किया गया है ;

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि मे कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजपथ बनाये जाने की योजना है और

(ग) इनके निर्माण मे पिछड़े क्षेत्रो मे परिवहन की समस्या कहा तक हल हो जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 1-4-1947 से आरम्भ हुई । उस समय (1-4-47) राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के अन्तर्गत आने वाली सडको की कुल लम्बाई 21,440 किलोमीटर थी, जो कि इस समय बढकर 28,819 किलोमीटर हो गई है । सलग्न विवरण मे 28.819 किलोमीटर की इस कुल लम्बाई का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है ।

इनमे से बहुत-सी सड़के पहले से ही मौजूद थी । पर इनको राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के स्तर तक लाने के लिए उनकी कमियों को दूर करके विकसित करने की आवश्यकता थी, कमियां जैसे छूटे हुए सड़क के टुकड़े, निम्न स्तर के खण्ड, बिना पुल के नदियो के पार पथ, कमजोर और तंग पटरियां संरचनाएं। धन की उपलब्धता के अनुसार कमियां दूर की जा रही हैं ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में लगभग 40,000 किलोमीटर की वृद्धि करने के प्रस्ताव विभिन्न राज्यो, स्थानीय प्रशासनो और अन्य प्राधिकारियों की ओर से प्राप्त हुए है । पांचवीं योजना में इस माग की पूर्ति करना कहां तक सम्भव होगा, यह कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे—पांचवी योजना मे इस प्रयोजन के लिये योजना आयोग द्वारा उपलब्ध किये जाने वाली धन राशि, अखिल भारतीय आधार पर प्रत्येक योजना की पारस्परिक प्राथमिकताए और राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप मे सड़कों को घोषित करने के लिए निर्धारित कसौटी ।

समस्त देश की आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए ही राष्ट्रीय राजमार्गों का आयोजन और विकास किया जाता है, न कि किसी विशेष क्षेत्र और इलाके के आधार पर । राष्ट्रीय राजमार्ग अन्य बातो के साथ साथ उन पिछड़े हुए क्षेत्रों की सेवा करते हैं जो उनके मार्ग पर पड़ते हैं । पर निश्चित रूप से कहना सम्भव नही है कि वर्तमान राजमार्गों के विकास और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त बनने वाले मार्गों द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों की यातायात की समस्या कहा तक हल हो सकेगी । केवल यही कहा जा सकता है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के अकेलेपन को समाप्त करने और उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने में एक सुधरी हुई और विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति, निश्चित रूप से सहायक होगी ।

किलोमीटरों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	चौथी योजना के प्रारम्भ में अर्थात् 1-4-69 को लम्बाई	चौथी योजना के दौरान शामिल की गई सड़कों की लम्बाई	कुल लम्बाई किलो मीटरों में	अभ्युक्ति
1	आन्ध्र प्रदेश	2299	—	2299	
2	असम	1190	462	1652	243 किमी० सीमा पथ विकास बोर्ड के पास
3	बिहार	1867	250	2117	
4	चण्डीगढ़	—	24	24	
5	दिल्ली	72	—	72	
6	गोआ	—	229	229	
7	गुजरात	1082	270	1352	
8	हरियाणा	729	—	729	
9	हिमाचल प्रदेश	398	232	630	306 ½ किमी सीमा पथ विकास बोर्ड के पास
10	जम्मू और कश्मीर	541	—	541	सीमा पथ विकास बोर्ड के पास
11	केरल	416	317	733	
12	मध्य प्रदेश	2670	—	2670	
13	महाराष्ट्र	2379	482	2861	
14	मणिपुर	211	—	211	
15	मेघालय	161	—	161	
16	मैसूर	1306	690	1996	
17	नागालैंड	110	3	113	
18	उड़ीसा	1363	286	1649	
19	पंजाब	448	417	865	
20	राजस्थान	1251	906	2157	
21	सिक्किम	62	—	62	सीमा प० वि० बोर्ड के पास
22	तामिलनाडु	1698	51	1749	
23	त्रिपुरा	—	200	200	प्रयोजित
24	उत्तर प्रदेश	2328	—	2328	
25	पश्चिमी बंगाल	1419	—	1419	
	योग	24000	4819	28819	1352 किमी० सीमा प० वि० बो० के पास

श्री चिरंजीव झा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो विवरण दिया है उसमें लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अन्य बातों के साथ साथ उन पिछड़े हुए क्षेत्रों की सेवा करते हैं जो उनके मार्ग पर पड़ते हैं। पर निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है कि वर्तमान राजमार्गों के विकास और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त बनने वाले भागों द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों की यातायात की समस्या कहां तक हल हो सकेगी।

जब कभी पिछड़े हुए क्षेत्रों की बात उठती है, उनके आर्थिक विकास, कृषि विकास के लिये, तो बराबर यही सवाल आता है कि यातायात के अभाव में वहां पर उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकते और कृषि के विकास में बाधा आती है। तो मैं पूछना हूं कि जब योजना आयोग के द्वारा देश भर के पिछड़े जिलों के नामों की घोषणा कर दी गयी है, तब आगानी मे बताया जा सकता है कि राज्य के किस जिले मे हो कर कितने मील लम्बाई के राज मार्ग गुजरते हैं। परिवहन की सुविधा न होने के कारण ही न तो वहां उद्योग ही स्थापित किये जा सकते हैं और न कृषि का विकास ही सम्भव है। तो पंचवर्षीय योजनाकाल में उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में राष्ट्रीय राज मार्ग के विकास के लिये आप कोई विचार रखते हैं ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य का प्रश्न था कि उनके निर्माण में पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन की समस्या कहां तक हल हो जायगी ? केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ही पिछड़ापन दूर नहीं हो पाता है, उनके साथ-साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का मिलान के लिये सड़कें चाहियें वह होनी चाहियें, और जो कमियां हैं जैसे छूटे हुए सड़क के टुकड़े, निम्न स्तर के खण्ड, बिना पुल की नदियों के पार पथ आदि ये सब कमियां जब दूर हों तब यातायात की सुविधा हो सकती है। चूंकि इन तीनों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है इसलिये उनसे सम्पर्क बनाया जा सकता है।

नये राष्ट्रीय राजपथों के लिये उत्तर प्रदेश उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों में विचार-विमर्श

*362. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग सहित भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से गुजरने वाले नये राष्ट्रीय राजपथों संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा करने हेतु 29 और 30 जनवरी 1971 को उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा भारत सरकार के सबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) क्या उक्त बैठक में मुख्य निदेशक (सड़क परिवहन) ने कहा था कि मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तावित कुछ सड़कें राष्ट्रीय राजपथ घोषित किये जाने योग्य हैं, और

(ग) क्या इन सड़कों को अभी तक राष्ट्रीय राजपथ घोषित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) सम्भवतया सदस्य महोदय का आशय सयुक्त योजना वर्ग की परिवहन और सचार समिति की विशेष बैठक से है जिसे योजना आयोग ने दक्षिण पूर्वी साधन क्षेत्र के लिये जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और उड़ीसा के भाग शामिल हैं के लिये एक क्षेत्रीय योजना बनाने के लिए गठित की गई थी। यह बैठक दिल्ली में 29 तथा 30 जनवरी 1971 को हुई थी जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई थी जिनमें नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्रस्ताव का विषय भी शामिल था।

2. इस बैठक में, इन चार राज्यों में कई नई सड़कें राष्ट्रीय राज्य मार्ग पद्धति में